फूड मिनिस्ट्री ने ₹2000 और कृषि मंत्रालय ने ₹3500 प्रति टन इनसेंटिव की सिफारिश की

रॉ शुगर प्रॉडक्शन और एक्सपोर्ट इनसेंटिव पर आज होगा फैसला

[माधवी सैली | नई दिल्ली]

कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) की गुरुवार को मीटिंग हो रही है, जिसमें रॉ शुगर प्रॉडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए शुगर इंडस्ट्री को इनसेंटिव देने के बारे में फैसला हो सकता है।

फूड मिनिस्ट्री ने रॉ शुगर प्रॉडक्शन और एक्सपोर्ट में इंडस्ट्री को 2,000 रुपये प्रति टन का इनसेंटिव देने की सिफारिश की है। वहीं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसके लिए 3,500 रुपये प्रति टन का सुझाव दिया है। फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने कहा, 'हमने रॉ शुगर प्रॉडक्शन और इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दो साल तक 2,000 रुपये प्रति टन का इनसेंटिव देने का सुझाव दिया है। कैबिनेट गुरुवार को इस पर विचार कर सकती है।' भारत में पिछले यानी 2012-13 शुगर सीजन में 80,000 टन रॉ शुगर का प्रॉडक्शन हुआ था। थॉमस ने बताया कि इनसेंटिव की रकम के बारे में कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरीज ने फैसला किया है।

हालांकि शुगर इंडस्ट्री 3,500 रुपये प्रति टन के इनसेंटिव की मांग कर रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी इंडस्ट्री को इतनी राहत देने की बात कही थी। इस पर एक इंडस्ट्री एग्जिक्यूटिव ने कहा, 'भारत में रॉ शुगर की प्रॉडक्शन कॉस्ट 2,600 रुपये प्रति टन है। वहीं ब्राजील की चीनी अभी इंटरनेशनल मार्केट में 14.85 सेंट्स प्रति पाउंड के भाव पर मिल रही है। इस हिसाब से भारत के लिए एक्सपोर्ट प्राइस 2,300 रुपये प्रति टन होता है।' उन्होंने कहा कि इस वजह से इनसेंटिव ज्यादा होना चाहिए। फूड मिनिस्ट्री ने रॉ शुगर प्रॉडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए 15 दिन पहले 2,400 रुपये प्रति टन के इनसेंटिव का सुझाव दिया था। तब थॉमस ने कहा था कि इनसेंटिव शुगर डिवेलपमेंट फंड (एसडीएफ), राज्यों और शुगर मिलों के जरिये दिया जाएगा। हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा था कि इनसेंटिव का पूरा बोझ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में नए प्रॉडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन की सिफारिशों के मुताबिक, भारत सरकार ने रॉ शुगर सेक्टर की मदद की बात की है।

> **फूड मिनिस्ट्री** ने रॉ शुगर प्रॉडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए 15 दिन पहले 2,400 रुपये प्रति टन के इनसेंटिव का सुझाव दिया था

इसी महीने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की लीडरशिप में मंत्रियों के समूह की मीटिंग में दो साल में 40 लाख टन रॉ शुगर के एक्सपोर्ट के लिए इनसेंटिव देने पर मुहर लगी थी। सरकार यह सब्सिडी मिल से बंदरगाह तक शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए दे सकती है। इससे उन मिलों को ज्यादा फायदा होगा, जो बंदरगाह के करीब हैं।

The Economic Times.
30-1-14.